शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में संचार-सुविधाएं

*402. श्री कपिल सिब्बल:
श्री राजीव रंजन सिंह:†

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में संचार-सुविधाएं बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या परतिक्रिया है;

(ग) क्या संचार विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये संचार विभाग द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

यद्यपि, यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या अधिक है, ऐसा मुख्यतः इस तथ्य के कारण है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की मांग कम थी। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग बढ़ रही है और विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के सभी प्रयास कर रहा है।

पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है, दूरसंचार प्रचालन विभाग इस समय देश में 2,74,20,192 सीधी एक्सचेंज लाइनों का प्रचालन कर रहा है। जिनमें से 49,26,287 सीधी एक्सचेंज लाइनें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह प्रचालन देश के 28,204 टेलीफोन एक्सचेंजों के माध्यम से किया जा रहा है जिनमें से 21,879 टेलीफोन एक्सचेंज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसके अतिरिक्त 6.07 लाख गांवों में से 3,76,886 गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष 2000-2001 में देश में (एमटीएनएल सहित) कुल 57.9 लाख लाइनें और प्रदान करने की योजना बनायी गयी है जिनमें से 14.2 लाख लाइनें, ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने हेतु योजनाबद्ध किये गये 3,431 नये एक्सचेंजों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के मौजूदा एक्सचेंजों के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी। वर्ष 2001-2002 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 19 लाख लाइनें प्रदान किये जाने की योजना है।

---

†सभा का यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा पूछा गया।

सरकार ने नीति के रूप में यह निर्णय लिया है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से सम्पूर्ण देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध किए जाएंगे। सरकार की यह भी परिकल्पना है कि 9वीं योजना के अंत तक देश के सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान कर दिए जाएंगे। नई दूरसंचार नीति-1999 में यह भी परिकल्पना की गयी है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के प्रत्येक गांव में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

Extent of Communication Facilities in the Rural Areas vis-a-vis Urban Areas

†*402. SHRI KAPIL SIBAL:
SHRI RAJIV RANJAN SINGH:††

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the rural areas in the country have lesser communication facilities as compared to the urban areas;

(b) if so, what is Government's reaction thereto;

(c) whether the attention of the Department of Communications has been drawn towards the same; and

(d) if so, when and what assurance has been given by the Department of Communications to provide the communication facilities in the rural areas?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Although it is a fact that the urban telephone connections are higher as compared to rural areas, this is the mainly due to the fact that earlier the demand for telephones was less in rural areas, however, now the demand for rural areas is also

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh.

coming up and Department is making all out efforts to cope up with the demand of the rural areas.

The tecom facilities in rural areas have progressed considerably over the last few years. Presently, Department of Telecom Operations is operating 2,74,20,192 Direct Exchange Lines (DELs) in the country out of which 49,26,287 DELs are working in rural areas. This is being done through 28,204 telephone exchanges in the country out of which 21,879 are in rural areas. In addition, out of 6.07 lakh villages, Public Telephones have been provided in 3,76,886 villages. It is further planned to provide a total of 57.9 lakh lines in the country (including MTNL) in the current financial year 2000-2001, out of which 14.2 lakh lines will be in rural areas through the existing exchanges in rural areas as well as 3,431 new exchanges planned for opening in rural areas. It is also planned to provide 19 lakh lines in rural areas during 2001-2002.

The Government has decided as a policy, to make available Telephone on Demand by the end of Ninth Five Year Plan in the entire country which includes both rural as well as urban areas along with the contribution of private sector. The Government has also envisaged that all the exchanges in the country will be covered with reliable transmission media by the end of Ninth Plan. The New Telecom Policy—1999 also envisages that each village in the country will have at least one Public Telephone by the end of Ninth Five Year Plan along with the contribution from Private Sector. All out efforts are being made to achieve these targets.

श्री राजीव रंजन सिंह: महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसके खंड तीन में यह कहा है कि "निजी क्षेत्र के सहयोग से सम्पूर्ण देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध करा दिये जाएंगे।" महोदय, जब यह एक बार निजी क्षेत्र को जाएगा तो निजी क्षेत्र का जो दृष्टिकोण होता है, वह पूर्णतः व्यावसायिक होता है और ग्रामीण क्षेत्रों की जो संचार व्यवस्था है, वह लाभकारी नहीं है। तो जो निजी क्षेत्र उसमें लगाए जाएंगे, वे सारे शहर की संचार व्यवस्था पर केन्द्रित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की जो योजना है, उस पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन निजी क्षेत्रों का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर ही केन्द्रित रहे, इसके लिए क्या कोई सख्त निर्देश दिये गये हैं या ऐसी कोई योजना सरकार के पास है?

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Sir, I want to seek one clarification.

MR. CHAIRMAN: On what? *(Interruptions)* No; no. *(Interruptions)* On what? *(Interruptions)*

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Sir, the second question is also being put by the same Member.

MR. CHAIRMAN: It is a separate question. *(Interruptions)* Let him answer the question. *(Interruptions)* The hon. Minister is answering the question put by Shri Rajiv Ranjan Singh. *(Interruptions)*

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Two questions on the same day... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: What question? *(Interruptions)* No; no.

श्री राम विलास पासवान: महोदय, माननीय सदस्य की जो शंका है, वह सही है कि जो हमारा लक्ष्य है कि 2002 ईस्वी तक हम हर गांव को टेलीफोन सुविधा देंगे और उसमें प्राइवेट सैक्टर के जिम्मे यह काम सौंपा गया है और टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक प्राइवेट सैक्टर ने अपनी जवाबदेही को नहीं निभाया है और 98000 गांवों में से केवल 12 गांवों में उन्होंने टेलीफोन लगाने का काम किया है लेकिन सरकार का वादा है कि 2002 तक देश के हर गांव में, 6 लाख 07 हजार गांवों में टेलीफोन लाइन की सुविधा देंगे। इसके लिए हम उपाय कर रहे हैं और अभी तक 3,76,886 गांवों में टेलीफोन लाइन की सुविधा दे दी गयी है। हालांकि उसमें 2 लाख 11 हजार गांव "मार टेक्नोलॉजी" के तहत हैं जो कई जगहों पर सही ढंग से काम नहीं कर रही है, उसको हम डब्ल्यू॰एल॰एल॰ से बदलने जा रहे हैं। वहीं इस बार हमारा लक्ष्य एक लाख गांवों का है। उसके लिए टी॰आर॰ए॰आई॰ को हम लोगों ने आग्रह किया है कि जो सोशल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड है, उसको लेवी के रूप में लगा दें। वह लेवी प्राइवेट सैक्टर पर भी लगेगी और गवर्नमेंट के ऊपर भी लगेगी। उससे जो पैसा आएगा, वह पैसा ग्रामीण टेलीफोनी के ऊपर लग जाएगा। उसके बावजूद भी यदि ग्रामीण टेलीफोन के संबंध में पैसे की कमी रहेगी तो जो हमारा रैवेन्यू शेयरिंग का पैसा है, उसको भी सरकार सोच रही है कि विलेज टेलीफोन के लिए रिजर्व रखा जाए। किन्तु जो हमने वादा किया है कि 2002 तक हर गांव में टेलीफोन लगाएंगे, उस वायदे को जरूर पूरा किया जाएगा।

श्री राजीव रंजन सिंह: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि जो निजी क्षेत्र है, उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन्स एग्रीमेंट किया था, उसके अनुरूप काम नहीं किया है और आगे मंत्री महोदय की भी आशंका है कि वे उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो मेरा (क) प्रश्न यह है कि

इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और (ब) यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की जो व्यवस्था है, उस पर प्रशासनिक नियंत्रक के लिए... जो आज उनका प्रशासनिक नियंत्रण है वह तो शहरों पर ही केंद्रित है तो उसके लिए क्या कोई अलग प्रशासनिक ढांचा भी खड़ा करना चाहते हैं?

श्री राम विलास पासवान: सर, हमने बतलाया कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ही हमने कहा कि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, उसको हम वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रख रहे हैं और जहां तक विलेज टेलीफोनी का सवाल है, हमारे पास फिगर्स हैं कि आज से कुछ समय पहले 1995-96 में जहां रूरल टेलीफोनी पर 11 परसेंट खर्चा होता था वहीं पिछली बार रूरल टेलीफोनी पर 24 परसेंट खर्चा किया गया है। इस बार हमने नीति बनाई है और हमने अपने अधिकारियों से और कमीशन से भी कहा है कि रूरल टेलीफोनी के लिए वे कम से कम 33 परसेंट खर्च के लिए रखें जिससे कि हमारा टारगेट पूरा हो। दूसरे, हमने अपने डिपार्टमेंट में तीन सेल खोले हैं। एक सेल खोला है जो रूरल टेलीफोनी की मॉनीटरिंग करने का काम करता है सीनियर डी॰ डी॰ जी॰ की अध्यक्षता में। दूसरा सेल टेलीफोनी के कस्टमर का जो मामला है, वह हमने अपने अधीन ग्रीवेंस सेल खोल रखा है और तीसरा सेल वर्ल्ड क्लास टेक्नालॉजी के लिए भी हमने जो सीनियर डी॰ डी॰ जी॰ हैं, उनकी अध्यक्षता में खोला है। तो मॉनीटरिंग का काम जारी है और वह काम प्रॉम्पटली किया जा रहा है।

कुमारी फ्रिडा टोपनो: चेयरमैन सर, मैं अपने क्षेत्र विशेषकर अपने कंस्टीट्युएंसी एरिया के लिए बोल रही हूं जो कि पूरा रूरल एरिया है। 1999 की नई पॉलिसी के तहत हरेक गांव में नाइन्थ फाईव ईयर प्लान के आखिर तक कम से कम एक टेलीफोन दिए जाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पर नाइन्थ फाईव ईयर प्लान के आखिर तक सब जगह ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैं विश्वास नहीं करती हूं। खुद मेरी कंस्टीट्युएंसी में जिसे ''मार'' सिस्टम बोलते हैं, वह टेलीफोन है। बीस से पच्चीस साल हो गए लेकिन एक भी दिन उस पर टेलीफोन नहीं किया जा सका है। वहां के सी॰ जी॰ एम॰ से भी मैंने रिपोर्ट की थी, सबको कहा लेकिन वे लोग कहते हैं कि वहां रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। वह टेलीफन पोस्ट ऑफिस में है। यदि वह ठीक हो जाता तो कम से कम पब्लिक कॉल करने के ही काम आ जाता पर वह भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी हालत में हरेक गांव में आप एक टेलीफोन लाईन देंगे, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता है। तो इस ''मार'' सिस्टम को चेंज करके डायरेक्ट एक्सचेंज लाईन देना अच्छा होगा इसलिए मैं मंत्री महोदय से आपके ज़रिए से अर्ज़ करना चाहती हूं कि कम से कम यह चीज़ होनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान: सर, मैंने शुरू में ही कहा कि जो ''मार'' सिस्टम है, ''मार'' टेक्नालॉजी है, वह सब जगहों पर काम नहीं कर रही है और लगभग पचास से साठ परसेंट जगहों

पर काम नहीं कर रही है। उसमें एक खामी यह हुई कि जिनसे टेक्नालॉजी ली गई, उनसे मेंटेनेंस का प्रोविज़न नहीं रखा गया लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम अब उस टेक्नालॉजी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं और इस तरह की टेक्नालॉजी 2 लाख 11 हज़ार गांवों में है और इस साल हम 1 लाख 11 हजार गांवों को डब्ल्यू० एल० एल० जो नई टेक्नालॉजी है और बहुत ही रिलायेबल है, जिसे एक जगह लगाने पर 25 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी एप्रोच के वह टेलीफोन की सुविधा दे सकता है, उस टेक्नालॉजी को हम ला रहे हैं। हमने ऑलरेडी 6 लाख टेंडर कर दिया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब वह टेक्नालॉजी आएगी तो जो गांव हमारे पास बचे हुए हैं, जो दूर-दराज के गांव हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं या फ्लड एरियाज़ हैं जहां हम नॉर्मल केबल के द्वारा टेलीफोन नहीं पहुंचा सकते हैं, पहले हम उनकी व्यवस्था करेंगे और काम करेंगे। रूरल टेलीफोनी के बारे में मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कि बहुत चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं लेकिन वे नहीं हो पाती हैं। हमको इस बात का दुख़ है कि पिछले तीन महीने से हमारा पूरा केबल का काम रुका हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है ओएफसी और जैली फील्ड केबल्स। इसका मामला जबलपुर कोर्ट में चला गया है और जबलपुर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर रखा है। अभी एक हफ्ता पहले क्लियर होकर वह फिर डिवीजन बैंच में चला गया। वह मध्य प्रदेश का एक पब्लिक सैक्टर है। उसमें यह मामला पड़ा हुआ है। अप्रैल, मई और जून का समय सबसे बैस्ट पीरियड होता है, क्योंकि बरसात में काम धीमी गति से चलता है। हम लोगों ने एप्रोच की है, कोर्ट में मामला है जैसे ही वह हो जाएगा हम दोनों तरफ से काम करना शुरू कर देंगे। एक तरफ से ऑप्टीकल फाइबर केबल के माध्यम से और दूसरा मैंने कहा कि डब्ल्यूएलएल के माध्यम से। वैसे मेरे पास जिन माननीय सदस्य की शिकायत आती है उन पर हम प्रोम्पटली एक्शन लेते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद भी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने 45 लाख का लक्ष्य रखा था उसके अगेंस्ट पूर्ति करते हुए हमने करीब 50 लाख कनैक्शन देने का काम किया है। जैसा मैंने कहा कि हम स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बारे में शिकायत नहीं होने देंगे।

डॉ० अलादी पी० राजकुमार: सर मैं मंत्री महोदय से एक सीधा-सादा प्रश्न पूछना चाहता हूं अभी हमारे देश के कितने गांवों में टेलीफोन फैसिलिटी नहीं है तथा प्रत्येक राज्य के अंदर कितने विल्लेज बाकी हैं और इसके लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? इसको कब तक कम्पलीट करके हर एक विल्लेज में टेलीफोन फैसिलिटीज देने का विचार है?

श्री राम विलास पासवान: सर, जैसा मैंने अभी कहा कि कुल मिलाकर 2,32,886 गांवों में अभी टेलीफोन की सुविधा नहीं है। हमारा टार्गेट है कि 31 मार्च, 2002 तक हम हर गांव में टेलीफोन की सुविधा दे देंगे।

श्री विजय जे० दर्डा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों

के अंदर टेलीफोन योजना के तहत जो कनैक्शन्स हैं उनकी हालत बहुत गंभीर है। यह सही है कि आपका लक्ष्य सन् 2002 तक देश के हर गांव में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का है। आप स्वयं जानते हैं कि आपके आने के बाद इस देश की उम्मीदें काफी जगी हैं और आपके सोशल कमिटमेंट के बारे में लोगों को विश्वास है। इसके बावजूद भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने 1700 गांवों में विजिट करने के बाद पाया कि उन सभी गांवों में टेलीफोन कई वर्षों से बन्द पड़े हुए हैं। टेलीफोन कोई एन्टरटेनमेंट की वस्तु नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में वह जीने मरने के लिए एक उपयोगी साधन है।

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

श्री विजय जे॰ दर्डा: इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आज जो सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, जैसा आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर टेलीफोन व्यवस्था ठीक हो जाएगी, मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक ठीक होगी?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, माननीय सदस्य ने दो बातें कहीं—एक है टेलीफोन की सुविधा और दूसरा है टेलीफोन का सही ढंग से काम नहीं करना। मैं इस बात से सहमत हूं कि ग्रामीण इलाकों में जहां टेलीफोन एक्सचेंजस हैं वहां टेलीफोन के रखरखाव की प्रॉब्लम्स हैं और काफी जगहों पर टेलीफोन लाइन्स काम भी नहीं कर रही हैं। लेकिन इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इस समय देश में दो लाख किलोमीटर एरिये में पेपर केबल्स चल रही हैं। आज हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। ये पेपर केबल्स जहां लगाकर रखते हैं वहां अगर थोड़ा-सा भी पानी पड़ता है तो इनके खराब होने का डर रहता है। इसलिए हमने तय किया है कि तीन साल के अंदर पेपर केबल्स को रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह डब्ल्यू॰ एल॰ एल॰, ओप्टिकल फाइबर, जेलिफिल आदि जो बढ़िया टैक्नोलॉजी हैं उन्हें लाने का काम करेंगे।

दूसरा, आजकल प्राइवेट सेक्टर्स और अन्य कई सेक्टर्स आ रहे हैं। कहीं रोड की खुदाई होती है क्योंकि नीचे केबल डालना होता है तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत जगह पर हमारे पास मैनपावर की कमी है, बिजली की कमी है और जहां तक लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल है इसकी भी स्थिति खराब है। एक जगह जहां सरकार की नीति डाउनसाइज करने की है तो दूसरी जगह हमारा काम बढ़ता जा रहा है। पिछले तीन साल में जितने टेलीफोन कनेक्शन्स दिए गए हैं उतने पिछले पचास साल में भी नहीं दिए गए थे। लेकिन हमने कहा है कि हम सारे टेलीफोन एक्सचेंजस को रिलायबल मीडिया से जोड़ रहे हैं और मार्च, 2002 तक हम इसे डिजिटल रिलायबल मीडिया से जोड़ने का काम कर देंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तीन साल का हमारा यह केबल बदलने का कार्यक्रम है लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से सुधार आ रहा है। यह सुधार लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, संचार

ढाबा की बात कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर हम यह संचार ढाबा ला रहे हैं। इस संचार ढाबा से न सिर्फ इंटरनेट की फेसिलिटी मिलेगी बल्कि पंचायत स्तर पर हर टेलीफोन सुविधा देने का काम भी होगा। इसके लिए हमारे पास रिलायबल मीडिया, एक्सचेंज और केबल होना जरूरी है तथा इसके लिए हमारा चौतरफा प्रयास जारी है।

प्रो॰ राम गोपाल यादव: सभापति महोदय, यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में दूरसंचार के क्षेत्र में जबर्दस्त क्रांति आई है यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो टेलीफोन दिए जा रहे हैं उनमें एक तरफ तो कनेक्शन दिए जाते हैं और दूसरी तरफ वे खराब होना शुरू हो रहे हैं। मैकेनिकल डिफेक्ट हो सकता है लेकिन मैं अपने गृह जनपद के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सबसे बड़ी कमी पोस्टड अधिकारियों की लापरवाही की वजह से होती है। गरामीण क्षेत्र में जितने एक्सचेंज हैं उनमें कोई अधिकारी रहता ही नहीं है। हमारे क्षेत्र में अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगा हुआ है, सारी सुविधाएं हैं लेकिन कोई अधिकारी नहीं रहता इसलिए महीने में पंद्रह दिन एक्सचेंज खराब रहता है। हगारा एक्सचेंज पिछले पन्द्रह दिनों से बंद है। हम अपने कॉलेज और घर पर टेलीफोन नहीं कर सकते। स्वयं बेनी प्रसाद वर्मा जी ने उसका उद्घाटन किया था। ए वन एक्सचेंज है लेकिन वहां के अधिकारी के बारे में पता चला कि वह तीन दिन कानपुर रहता है, हेडक्वार्टर इटावा में तो रहता ही नहीं है। यदि इस तरह के अधिकारी होंगे तो आप इन क्षेत्रों में कितने भी कनेक्शन्स दीजिए वे चल नहीं सकते। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश में आप ऐसी कोई व्यवस्था अपनाने की योजना बना रहे हैं जिससे कि आप एक्सचेंज पर अपने अधिकारी रखना सुनिश्चित कर सकें?

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, लवेल प्लेइंग फील्ड दिया गया है, कम्पीटीशन लाया गया है। एक अक्तूबर से पूरा डी॰ टी॰ एस॰ डिपार्टमेंट कार्पोरेटाइज होने जा रहा है। जब कॉर्पोरेटाइजेशन होगा तो कंपनी बनेगी। कम्पीटीशन में प्राइवेट सेक्टर के साथ उन्हें कम्पीटीशन करना पड़ेगा। जो कम्पीटीशन करेगा वह सरवाइव करेगा। जो नहीं करेगा वह नहीं रह पाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने कहा लाइन का, एक दूसरा है इन्स्ट्रूमेंट का, इनके लिए नियम भी ऐसा बना हुआ था कि अगर इन्स्ट्रूमेंट खराव भी हो जाए उसको बदला नहीं जाएगा क्योंकि उसकी लाइफ दस साल थी। दस साल तक उसको बदला नहीं जा सकता था। इसकी सीजीएम को भी पावर नहीं है। इसी प्रकार ओवर-हेड वायर यदि कहीं कट जाए तो उसको भी बदलने का प्रावधान नहीं था। हमने इसके लिए एक कमेटी वनाई और पन्द्रह दिन में उसकी रिपोर्ट ली। अब हमने इन्स्ट्रूमेंट की लाइफ दस साल न रखकर उसको पांच साल कर दिया है। हमने कस्टमर्स को यह भी सुविधा दी है कि यदि वे चाहें—अब यह उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वह इन्स्ट्रूमेंट हम से ही खरीदें, अब 500 रुपया रिवेट रहेगा और उस 500 रुपए में और कुछ पैसा लगाकर आप बढ़िया से बढ़िया इन्स्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं। सीजीएम को हमने पावर दी है कि अगर जरूरत पड़े तो वे तार भी बदल सकते हैं, उसको

रिप्लेस भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद भी हम स्वयं भी विजिट करते हैं। हम नेहरू प्लेस में गए थे और वहां के डीजीएम को इमीडिएटली सस्पेंड करने का भी हमने काम किया था। उसके अलावा भी ...(व्यवधान)... देखिए हम गांवों में ऐक्शन ले सकते हैं लेकिन 90 परसेंट जगहों पर जहां ऐक्शन लेते हैं वहां तुरन्त पैरवी पहुंच जाती है और पैरवी पहुंचती है माननीय संसद सदस्यों की अधिक। इसलिए यदि हम एक कोड आफ कंडक्ट बना लें तो ठीक रहेगा। जैसा नार्थ-ईस्ट का इलाका है, जम्मू-कश्मीर का इलाका है, बिहार का इलाका है, इन तीनों जगहों पर कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता है, कोई कर्मचारी नहीं जाना चाहता है और यदि जाता भी है तो वहां रहना नहीं चाहता। नतीजा यह होता है कि हम पैसा भी खर्च करते हैं, पैकेज भी देते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता। नार्थ-ईस्ट को हम पैकेज दे रहे हैं लेकिन इसके कारण कभी कभी लाचारी हो जाती है। परन्तु इसके बावजूद भी हम स्ट्रिक्ट हैं। हमने नियम बनाया है अनलेस कोई जबर्दस्त कम्पलसन या कारण न हो, हम उनको कहते हैं कि जहां जिनकी पोस्टिंग हो वहां वह सेवा करें। इसके बाद भी यदि कोई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। एक तरफ हम कर्मचारियों के हित के लिए गाली सुनते हैं, फ्री टेलीफोन के नाम पर, दूसरी चीजों के नाम पर तो दूसरी तरफ हम उनकी तरफ से कोई कोताही भी नहीं देखना चाहते हैं। हम एक वर्क कल्चर पैदा करना चाहते हैं। वर्क फैसिलिटीज देकर हम उनसे काम लेना चाहते हैं।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this is in addition to what Mr. Rajkumar has asked. The hon. Minister hails from a rural area and is a person from the grass-root level of activity. It is really surprising that even after 50 years, 2,32,856 villages are yet to be connected by the telecommunication network. I would like to know whether the Government would go in for a State-wise and region-wise action plan in this direction, with a specific target and with a specific time frame. The hon. Minister has said that the private sector will be allowed in this field. Sir, as the resources with the Government of India are limited, they want to take the help of the private sector in setting up the tele-communication network. I would like to know whether the Government, while involving the private sector along with the tele-communication department, to reach its target within a stipulated time frame, would make it mandatory for the private sector to go to the rural sector of the region as well. Will the hon. Minister take this up as a challenge?

श्री राम विलास पासवान: सर, हमने आलरेडी ऐक्शन प्लान बनाया है। मेरे पास ऐक्शन प्लान है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो स्टेट-वाइज, एरिया-वाइज आलरेडी वह हमारे पास है और यदि आप कहें तो उसको सदन के पटल पर रख दूंगा।

डा० अलादी पी० राजकुमार: आप उसको मेंबर्स को सर्कुलेट कर दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: मैं मेंबर्स को सर्कुलेट कर दूंगा।

दूसरा आपने प्राइवेट सेक्टर के बारे में कहा। प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है। मैंने शुरू में ही कहा कि 98 हजार गांवों में उनको टेलीफोन लगाने थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाए। इसके लिए उनके खिलाफ ऐक्शन भी लिया गया है। उन्होंने जुर्माना भी जमा कर दिया है। लेकिन इन लोगों के लिए 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया जुर्माना शायद कोई बड़ी बात नहीं होती होगी। लेकिन उनको हम छोड़ नहीं रहे हैं। सर, मैंने वायदा किया था कि पांच स्टेटों में हम 15 अगस्त तक हर एक गांव में टेलीफोन लगायेंगे। यह मैंने घोषणा की थी और 15 अगस्त तक केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, हरियाणा और अंडमान-निकोबार, इन पांच स्टेटों में कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां टेलीफोन की सुविधा न हो। 15 अगस्त तक हमने प्राइवेट सेक्टर वालों को भी कहा था कि आप पंजाब में भी करो क्योंकि पंजाब के 1600 गांव उनके जिम्मे थे। लेकिन दुर्भाग्य से वे नहीं कर पाए। लेकिन हम 15 सितम्बर तक हर गांव में डीटीएस द्वारा, अपने डिपार्टमेंट द्वारा टेलीफोन लगायेंगे। इसमें जो पैसे हम लगायेंगे यह हम प्राइवेट सेक्टर से लेंगे। आंध्र प्रदेश में हमारे 6000 गांव बचे हैं। दो साल से वे प्राइवेट सेक्टर के जिम्मे हैं। लेकिन मैंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के भरोसे पर हम देश को नहीं छोड़ सकते हैं हमारी गवर्नमेंट का जो वायदा है हम उस वायदे का पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी जो जवाबदेही दी गई है उस जवाबदेही को हम पूरा करेंगे।

SHRI J. CHITHARANJAN: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has made a commitment that according to the New Telecom Policy of 1999, all the villages in India would be provided with public telephones. Now public telephones have been provided only in 3,76,886 villages. Still 2,32,986 villages are left out. All along, these jobs were carried out by the Department of Telecom. They were carrying out these jobs when they were making profits; and year after year they were making considerable savings. Now the whole sector has been opened up to the private sector. Especially, the profit earning sections are being offered to the private sector. As a result of this, the Department of Telecom is reaching a stage where it may not be possible for them to make profits and savings every year to

provide for public telephones in villages or invest in providing telephone connections in the rural areas. As the Minister himself has just now pointed out the private sector cannot be depended on, whatever commitment they may make. They may not do the job. If at all they do any job, it will only be nominal. Therefore, how is the Department going to provide funds for public telephone in all the villages and telephone connections in the rural areas by the end of the Ninth Five Year Plan?

श्री राम विलास पासवान: मैंने कहा कि through the new technology, Government will provide telephone facilities in all the villages. As the Member has correctly said, out of 6,07,000 villages, only 3,76,000 villages have been provided with telephone facilities. The rest of the villages do not have any telephone facilities. As I told the House, the Government has invited tenders for 6,00,000 WLL. By November, we will get that technology. I can assure the House that whatever target has been fixed for replacing the MARR system with WLL, we will achieve it. We propose to replace 1,11,000 MARR systems. About 1,00,000 new villages will be covered. We want the front load to be more. That is why whatever commitment we have made, that will be fulfilled.

So far as the other points of the Honourable Member are concerned, I have already answered them.

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, एक दांत खाने के लिए होता है और एक दांत दिखाने के लिए होता है। गांवों में जो टेलीफोन की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। यह अपने आप में बड़ा दुखद मामला है कि अभी भी एक तिहाई से ज्यादा हमारे गांवों में टेलीफोन नहीं हैं। लेकिन जहां पर टेलीफोन हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं कि जहां एक्सचेंज़ हैं, वहां लाइन नहीं है, लिमिटेड लाइंस हैं, लाइंस की कमी है और जहां लाइन है वहां केवल नहीं है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सचेंज़ के बारे में मैं जानता हूं, केपेसिटी नहीं है। वहां पर हमने सिर्फ दिखाने के लिए एक्सचेंज लगा दिये या पब्लिक बूथ खोल दिये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इंस्ट्रूमेंट बदलने वाला जो प्रश्न है, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो एक्सचेंज कम केपेसिटी वाले हैं, कम क्षमता वाले हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में सरकार क्या करने जा रही है?

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, हमारे पास वेटिंग लिस्ट का सवाल आता है, हम वेटिंग लिस्ट से चिंतित नहीं होते हैं क्योंकि वेटिंग लिस्ट बिजनेस के लिए जरूरी है। लेकिन

जहां कहीं भी हम समझते हैं कि वेटिंग लिस्ट ज्यादा दिन की है तो जो हमारे यहां एक सेल खोला गया है, वह मोनिटेरिंग कर रहा है। रूरल टेलीफोनी के लिए हमने कहा है कि जहां 60—70 परसेंट तक की केपेसिटी है, उस केपेसिटी के मुताबिक वह यदि एचीव करता है तो इमीडियेटली वहां पर केपेसिटी बढ़ाने का काम किया जाए और केपेसिटी को और बढ़ाया जा रहा है।

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, I think that the basic question for expanding telecome in rural areas is the ability of the network to cross-subsidise from the profits gained elsewhere, to fund the unremunerative operations in the rural areas. Now, I am given to understand that last year, when the TRAI started its effort to phase out cross-subsidies, the revenue loss registered by the Department of Telecome was Rs. 3000 crores. Mr. Chairman, the Minister himself has admitted that out of the 98,000 telephones that the private licensees were supposed to have commissioned, they commissioned only 12. Another bout of the so-called tariff re-balancing is already on cards. Therefore, what is going to happen in the coming days? That is part (a) of my question.

Part (b) of my question is this. You have mentioned about corporatisation. Now, we are given to understand that the consultants who were being appointed have suggested that within one year, 50 per cent of DTO, DoT, is going to be disinvested. Is that true? If that is true, if that is the experience of the private sector, what happens to these millions of villages which are as yet uncovered? This is a country where, according to your National Telecome Policy, you have to achieve a tele-density of seven by 2005. And the fact is that all these private companies that are coming, are moving in or around metro-cities. Therefore, addressing the question of tele-density depends on how fast we can address the requirements of rural telephony. And, in the light of the fact that our capacity to cross-subsidise is coming down and the functioning of the private sector cannot address the problem, what is going to happen?

श्री राम विलास पासवान: माननीय सदस्य ने तीन बातें पूछी हैं। पहला तो इन्होंने कार्पोरेटाइजेशन के संबंध में कहा है। कारपोरेटाइजेशन होने के बाद भी 100 परसेंट इक्विटी गवर्नमेंट की रहेगी। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरी चीज आपने सेवा के संबंध में कही है। तो आपने कंट्राडिक्ट्री प्रश्न भी किया और जवाब

भी दिया। उसमें हमारा सीधा सा है कि पब्लिक को इस बात से मतलब नहीं है कि टेलीफोन गवर्नमेंट लगा रही है कि प्रायवेट वाले टेलीफोन लगा रहे हैं या पब्लिक सेक्टर वाले लगा रहे हैं। पब्लिक को चाहिए बढ़िया से बढ़िया सस्ती दर पर टेलीफोन और सेवा। यह पब्लिक के, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में है और उसके दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा आपने टेलीडेन्सिटी का सवाल पूछा। आपने सही कहा कि हमारी पालिसी है, the Government's policy is that by 2005, the tele-density should go up to 7 per 100; and by 2010, the tele-density should go up to 15 per 100. Today, unfortunately, it is below 3 per 100 in comparison to the world average of 15-16 per 100. For that, we require a lot of money. By 2005, we require about 33 billion American dollars and by 2010, we require about 88 billion American dollars. That is why the Government thinks that the private sector, the public sector and the Government sector, all, should be given a level playing field, so that our rural telephony or world telephony target, our equipment target, could be fulfilled.

श्री गांधी आज़ाद: दिसम्बर, 1999 में बहुत लुभावने नारे दिए गए कि 50 परसेंट जमा करने पर कनेक्शन दिया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दौरान कितने कनेक्शन के लिए मांग की गयी और उसमें से आज तक कितने कनेक्शन लग गए, कितने शेष हैं और ये कब तक पूरे देश में लग जाएंगे?

श्री रामविलास पासवान: वह तो मैंने बता दिया है। पहले ही बता दिया।

...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Withdrawal of subsidy given to farmers of Punjab

*403. SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the World Bank has asked Government to instruct Punjab Government to withdraw subsidy/freebies given